विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) उच्च न्यायालयों के संबंध में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए) उच्चतम न्यायालय की बाबत इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इसे यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिये उपायों का पता लगाने के लिए, मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन 4 दिसबंर, 1993 को आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत किए गए संकल्पों की सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। सम्मेलन निर्वाचन याचिकाओं का विचारण करने संबंधी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रखने के पक्ष में भी था।

विवरण

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय का नाम	निर्वाचनों से सम्बन्धित लंबित मामलों की संख्या,	निम्नलिखित तारीखों को यथाविद्यमान
1	इलाहाबाद	45	30-06-93
2	आन्ध्र प्रदेश	2	31-12-93
3	मुंबई	10	31-12-93
4	कलकत्ता	10	30-06-93
5	दिल्ली	4	30-09-93
6	गुजरात	7	30-06-93
7	गुवाहाटी	75	30-06-93
8	हिमाचल प्रदेश	शून्य	31-12-93
9	जम्मू-कश्मीर	8	30-09-93
10	कर्नाटक	10	30-09-93
11	केरल	शून्य	31-12-93
12	मध्य प्रदेश	42	30-06-93
13	गद्रास	3	30-09-93
14	उड़ीसा	शून्य	31-12-93
15	पटना	50	30-06-93
16	पंजाब और हरियाणा	17	31-12-93
17	राजस्थान	4	30-06-93
18	सिक्किम	शून्य	30-06-93

High Court bench at Madurai

1448. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN Will the PRIME MINISTER be pleased o state the reasons for delay in opening a bench of Madras High Court in Madurai ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : No specific, complete proposal has been received from the Government of Tamil Nadu, in the light of recommendations of the Jaswant Singh Commission, in consultation with the Chief Justice of Madras High Court, for establishing a Bench of that High Court at Madurai.